

नयी चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में भारत— चीन सम्बन्ध

रमाकान्त¹

¹शोधार्थी राजनीति विज्ञान, एम0 ए0 (नेट) वी0 एस0 एस0 डी0 कालेज कानपुर

Received: 15 April 2024 Accepted & Reviewed: 25 April 2024, Published : 30 April 2024

Abstract

भारत चीन सम्बन्धों का उदय भारत की आजादी के साथ आरम्भ हुआ जिसमें कुछ शर्तों के साथ सम्बन्ध स्थापित किये गये जैसे चीन पश्चिमी देशों की भांति युद्ध, विस्तारवाद, आक्रामक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर बल दिया जायेगा आदि। भारत चीन सम्बन्ध बहुत प्राचीन काल से माने जाते हैं क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रचलन एवं दानों देशों में इसका सम्मान प्रचुरता से होता रहा है। समय रहते हुये दोनों देशों में सम्बन्ध बनते बिगड़ते रहे हैं लेकिन कोरोना काल में जिस तरह सभी देश चीन से निर्भरता खत्म करना चाह रहे थे ऐसा होना सम्भव नहीं है और इस प्रभाव से अछूता भारत भी नहीं है क्योंकि जहाँ अमेरिका संरक्षणवाद लेकर आगे बढ़ा वहीं चीन समाजवाद लेकर आगे बढ़ रहा है और रूचिकर बात यह है कि चीन आज विश्व में उदारीकरण नीति का प्रबल राज्य बनता जा रहा है। एशिया में जहाँ चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था से पैर फँला रखे है उसी प्रकार विश्व अर्थव्यवस्था में भी तेजी से आगे जा रहा है। चीन ने लगभग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना वर्चस्व कायम कर रखा है वहीं भारत की अपनी अलग समस्या है जैसे **RCEP** में चीन का होना भारत का न होना, **TPP** में चीन का होना आदि ऐसी स्थिति है जहाँ चीन बढ़चढ़ कर हिस्सा ले रहा है किन्तु भारत पीछे हो रहा हालांकि भारत की अपनी जरूरतें अलग हैं। कृषि प्रधानता आज भी है औद्योगिकीकरण भी उतना श्रेष्ठ गुणवत्ता का नहीं है फिर भी भारत के लिये चीन के परिप्रेक्ष्य में चुनौती बहुत अधिक है जिससे निपटने के लिये भारत सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैसले लेने की आवश्यकता है।

भारत में तकनीकी विकास चीन की तुलना में काफी धीमा है चीन जहाँ आज विश्व में ड्रैगन बनकर खड़ा है वहीं भारत की स्थिति अस्थिरता से गुजर रही है लेकिन धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। इसी कारण चीन भारत पर दबाव पूर्ण एवं विस्तारवादी नीतियों का पालन कर रहा है। हाल ही कि घटना गलवन घाटी, डोकलाम विवाद आदि घटित हुये जिसमें चीन की विस्तारवादी एवं साम्राज्यवादी नीति दिख रही है।

शब्द कुर्जी— भारत, चीन, विस्तारवादी, समाजवाद, सरकार, उदारीकरण, **RCEP** अर्थव्यवस्था, समझसैता, शीत युद्ध आदि।

Introduction

भारत एवं चीन के बीच सांस्कृतिक एवं भौगोलिक सम्बन्ध प्राचीन काल से विद्यमान है जैसा कि इतिहास से पता चलता है कि चीनी यात्री व्हेनसांग तथा फाहियान आदि आये और भारत की संस्कृति एवं सभ्यता का अध्ययन किया और भारत और चीन के सम्बन्ध के बारे में विस्तृत जानकार की जैसे प्राचीन काल में चीन के साथ रेशम का व्यापार आदि आगे बताया कि भारत एवं चीन एशिया की दो महा शक्तियां हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने चीन के साथ मधुर सम्बन्ध स्थापित

करने की प्रबल कोशिश की जिसका उदाहरण एशिया अफ्रीका एकता को सबल बनाने के लिये चीन के साथ प्रबल समर्थन किया और भारत चीन के सम्बन्धों का आरम्भ मित्रता पूर्ण हुआ लेकिन ये सम्बन्ध बहुत दिन तक स्थापित नहीं रह सके क्योंकि 1949 में जब चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई जिसका समर्थन भारत सरकार ने खुल कर दिया और आगे की नीतिया भी बनाई । लेकिन शीत युद्ध के दौरान चीन का प्रवेश यू0एन0ओ0 में होना था तो अमेरिका ने इसका विरोध किया लेकिन भारत ने चीन का समर्थन किया लेकिन चीन ने विस्तारवादी नीति का पालन करते हुये 1950 में तिब्बत पर अधिकार कर लिया जिसे भारत सरकार द्वारा मन्यता भी प्रदान की गई। आगे चलकर चीन ने मध्य राज्य का सिद्धान्त अपनाया जिसका अर्थ है चीन स्वर्ग के सबसे निकट है एवं विश्व में सबसे श्रेष्ठ है एवं धरती का केन्द्र बिन्दु भी चीन है एवं चीनी जाति ही सभ्य है बाकी सभी जातियां बर्बर है।

भाई— भाई सम्बन्ध :-

भारत चीन सम्बन्ध प्रारम्भ में सौहार्दपूर्ण रहे जिसका जीता जागता उदाहरण 1954 में हुआ पंचशील समझौता, जो जवाहर लाल नेहरू एवं चीनी प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई के मध्य नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ जिसके प्रमुख तत्व इस प्रकार है:-

- 1) एक दूसरे की क्षेत्रीय सम्प्रभुता एवं अखंडता का सम्मान करेंगे।
- 2) एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे।
- 3) परस्पर मित्रता एवं समानता की भावना रखेंगे।
- 4) एक दूसरे के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप नीति का पालन करेंगे।
- 5) शांति पूर्ण सह-अस्तित्व।

माओ की पांच उंगलियों का सिद्धान्त:- माओं ने पांच उंगलियों के सिद्धान्त में चीन को हाथ तथा तिब्बत को हथेली और नेपाल, भूटान, लद्दाख, सिक्किम, अरुणांचल प्रदेश को उंगलियों की सांझा दी है एवं चीन की विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादी नीति का खुलासा उपर्युक्त सिद्धान्त एवं 1962 में हुये भारत चीन युद्ध से होता है।

वर्तमान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नारा है—मेरे स्वप्न (My Dream)

भारत— चीन सम्बन्धों में कड़वाहट :- चीन की विदेश नीति प्ररम्भ से ही यथार्थवादी रही जिसके चलते चीन ने भारत चीन सीमा पहले ही मजबूत कर ली तथा 1957 में काराकोरम राज मार्ग का निर्माण भी कर लिया तथा 1959 में जब तिब्बत ने चीन के विरुद्ध आक्रमण कर दिया तब चीन ने तिब्बतियों का दमन नरसंहारता पूर्ण किया जिस कारण दलाई लामा सहित कई तिब्बती भारत में आ गये जिसका विरोध चीन ने किया।

अंततः चीन ने असली रंग 1962 में दिखा ही दिया और जिसमें चीन ने अरुणांचल प्रदेश (नेफा), लद्दाख पर जोरदार आक्रमण कर दिया एवं 1965 पुनः भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी विरोधी नीति चीन द्वारा प्रदर्शित की गई। जिसके चलते चीन ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया एवं 1974 में हुये भारत द्वारा पोखरन परमाणु परीक्षण का चीन ने खुलकर विरोध किया और इस परीक्षण को परमाणु ब्लैक मेलिंग

कहा तथा 1975 सिक्किम का भारत में विलय होना चीन को किसी भी स्थिति में मंजूर नहीं था इसलिये भारत चीन सम्बन्ध में खटास होती रही।

डेंगशियाऊ विंगः— 1980के दशक में महसूस किया कि दोनों देशों के बीच तनाव स्थिति ठीक नहीं है इसलिये सुधार की आवश्यकता है जिसकी पहल प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा की गई जो भारत चीन सम्बन्ध में सुधार के लिये उल्लेखनीय है।

शीत युद्ध के बाद भारत :- चीन सम्बन्ध ने विश्व युद्ध के बाद भारत चीन सम्बन्ध नांन जीरो सम गेम पर आधारित है विश्वयुद्ध के बाद पूरे विश्व में आशातीत सुधार हुआ लेकिन वहीं भारत को चीन के साथ सम्बन्ध स्थिर एवं अच्छे रखने के लिये सामरिक क्षमता निर्णय में वृद्धि करना होगा। विश्व युद्ध के बाद भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती हुयी दूसरी अर्थव्यस्था है जो दुनिया के 10 बड़े बाजारों में से एक है जिस कारण चीन को भारत के प्रति अपना नजरिया बदलना पड़ा।

सीमा विवाद का मुद्दा :- भारत चीन सीमा जिसका निर्धारण 1988 में राजीव गांधी की यात्रा के बाद जो परिवर्तन हुआ वो प्रमुख है जो भारत चीन के बीच अरुणांचल प्रदेश में मैक मोहन रेखा है द्वारा विभाजित है 1996 में एल0ए0सी0 पर शांति समझौता हुआ। 2003 में अटल बिहारी बाजपेई ने चीन यात्रा की एवं सीमा विवाद सुलझाने के लिये विशेष प्रतिनिधि मण्डल का गठन करवाया।

चीन की नीति भारत पर दबाव बनाने की है :-

- 1)चीन ने विश्व के सभी देश जो सीमा साझा करते हैं के साथ सीमा विवाद सुलझा लिया है लेकिन भारत के साथ अभी भी बाकी है।
- 2)चीन समूचे विश्व को दिखाना चाहता है कि हम विवाद नहीं चाहते लेकिन भारत सीमा विवाद हल नहीं चाहता।
- 3)भारत सीमा विवाद सुलझाने के लिये सीमा समाधान सेक्टर तथा चीन पैकेज की डीलिंग पर जोर दे रहा है।
- 4)चीन 90000 वर्ग कि०मी० भारतीय क्षेत्र को अपना होने का दावा करता है तथा अरुणांचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र को अपना कहता है जो भारत पर दबाव बनाने की नीति है।
- 5)**नोट :-** 1962 में चीन ने भारत के भू-भाग पर नियंत्रण कर लिया जिसमें 10 दर्रे (लद्दाख और तिब्बत) हैं जो भारत तिब्बत के मध्य आवागमन का मार्ग थे।
चीन ने अपने ई पासपोर्ट में अरुणांचल व अक्साई चीन को अपना भू-भाग दर्शाया है।

प्रमुख मुद्दे :-

कश्मीर मुद्दा – चीन कश्मीरी नागरिकों के लिये **स्टेपल वीजा** का प्रयोग कर रहा है जिसका अर्थ है कि कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है तथा कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है।

आतंकवाद का मुद्दा :- 2001 से दोनों देश आतंकवाद के खात्मे की बात कर रहे हैं।

वहीं अफगानिस्तान में बढ़ती गतिविधियां दानों के प्रतिकूल हैं दानों देशों के बीच भिन्नतायें हैं पाक के संदर्भ में चीन पाक को आतंकवाद प्रयोजित देश नहीं मानता जबकि भारत मानता है। 2016 में दोनों

देशों के बीच आतंकवाद समझौता भी हुआ लेकिन चीन ने पाक के आतंकी संगठन के नेता मसूद अजही तथा लश्कर-ए-तोयबा का नेता हाफिद सईद का समर्थन सुरक्षा परिषद के मंच पर किया जिसका विरोध भारत ने किया।

दोनों देश एक साथ— विश्व व्यापार संगठन में जलवायु परिवर्तन मुद्दे पर SCO में भारत पर्यवेक्षक ,दक्षेस में चीन पर्यवेक्षक

ब्रिक्स में दोनों साथ

वन बेल्ट वन रोड परियोजना पर बीजिंग में सम्मेलन — इसका आयोजन 14 मई 2017 में किया गया जिसमें 29 राष्ट्रध्यक्षों सहित 100 देशों ने भाग लिया USA तथा जापान ने चीन की कुटनीति के कारण विरोध किया ।

इस परियोजना के तहत चीन विश्व में 6 कारिडोर बनायेगा जिसमें रोड, रेलवे, हवाई, ऊर्जा, यातायात शामिल है तथा भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया भारत द्वारा चाइना पाक कारिडोर का विरोध किया जा रहा है क्योंकि इसके निर्माण से भारत कि सम्प्रभुता खतरे में पड़ जायेगी।

डोकलाम विवाद:— 2017 डोकलाम क्षेत्र एक पठारी भाग है जो भारत भूटान, चीन के मिलन बिन्दु चुम्बी घाटी पर स्थित है यह पठार पूर्णरूप से भूटान के अधिकार में है लेकिन चीन विस्तार वादी नीति के कारण इसे अपना होने का दावा कर रहा है । 2017 में चीन ने इसी क्षेत्र पर रोड निर्माण का कार्य शुरू किया जिसका विरोध भूटान के आग्रह पर भारतीय सेना ने किया जिसके चलते भारत-चीन विवाद शुरू हो गया तथा कार्य रूक गया । भारत का मानना है कि यह क्षेत्र भूटान का है जबकि चीन अपना दावा करता है लेकिन भारत के विरोध के बाद निर्माण रूक गया ।

वुहान शिखर सम्मेलन:— दोनों देश डोकलाम विवाद को छोड़कर सहयोग पर सहमत हुये 2018 मई में चीन ने मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने का समर्थन प्रस्ताव सुरक्षापरिषद को रखा।

RCEP की भूमिका में भारत की चीन के सापेक्ष चुनौतिया

इस संगठन में कुल 15 देश है जिनमें 10 आशियान एवं 3 आशियान और 3 (चीन, जापान, दक्षिण कोरिया) तथा आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड।

RCEP में विश्व की 30 प्रतिशत आबादी एवं 30 प्रतिशत ग्लोबल जी0डी0पी0 है वर्तमान में चीन उदारीकरण का प्रमुख अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है जिससे अंतर राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता का विकास हो रहा है एवं आर्थिक समूह गठित हो रहे है चीन वर्तमान स्थित में केंद्रित उदारीकृत राज्य के रूप में उभरा है।

भारत के लिये प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार है कि चीन के साथ जिन बड़े देशों के व्यापारिक सम्बन्ध है उन्हीं देशों के साथ अमेरिका के सामरिक सहयोग भी है जिनमें प्रमुख देश आस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया शामिल है इसलिये भारत विश्व मंच में खुद को अकेला नहीं झोड़ सकता है क्योंकि चीन के साथ

आशियान देशों के मुक्त व्यापार समझौते बने हुये है एवं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहीं न कहीं चीन पर भारत की निर्भरता बनी हुई है।

QUAD में शामिल भारत, जापान, आस्ट्रेलिया, अमेरिका है किन्तु ध्यान देने की बात है कि जापान और आस्ट्रेलिया के सम्बन्ध चीन के साथ अच्छे और स्थिर बने हुये हे इसलिये कह सकते है कि चीन का परोक्ष रूप से भारत के साथ सम्बन्ध स्थापित है।

RCEP में भारत क्यों नहीं :-

- 1) चीन के साथ व्यापार घाटा।
- 2) चीन के साथ परोक्ष समझौता होना(मुक्त व्यापार समझौता हो जायेगा)
- 3) चीन के साथ सीमा विवाद स्थित में सहयोग न होना ।

चुनौती

- 1) जापान ,दक्षिण कोरिया , आशियान के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता है।
- 2) इन्हीं से सहयोग हो रहा है एवं समीक्षा करने की आवश्यकता है क्योंकि इन्हीं देशों ने चीन के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता कर रखा है। इस प्रकार चीन की वस्तुयें भारत में आ ही जायेंगी इसे कैसे रोकना है ।
- 3) भारत अभी तक APEC का सदस्य नहीं है ।
- 4) भारत महा शक्ति के रूप में तैयार हो चीन के साथ अप्रत्यक्ष सम्बन्ध बने ही रहते है।

चुनौतियों से निपटने के प्रमुख आधार

- 1) वोकल फार लोकल को मजबूती प्रदान करना ।
- 2) मेक इन इंडिया को प्रभावी बनाना।
- 3) अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौता स्थापित करना
- 4) यूरोपीय यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौता स्थापित करना
क्योंकि यूरोपीय यूनियन से वस्तुयें पूरक मिलती है अर्थात जो वस्तुयें हम बेचते है उसके अलावा दूसरी वस्तुयें हमें खरीदने को मिलती है जो चीन पर निर्भरता कम करता है।
- 5) अफ्रीकी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता स्थापित करना।

निष्कर्ष:-

अंततः हम कह सकते है कि भारत चीन से निर्भरता कम करने के लिये चीन के साथ परोक्ष मुक्त व्यापार समझौता जो भी हुये उनकी अपेक्षा यूरोपीय ,अफ्रीकी, अमेरिकीय देशों के साथ भारत को अपने आर्थिक सम्बन्ध उच्च स्तर स्थापित करने की आवश्यकता है जिससे चीन से निर्भरता काफी हद तक कम हो जायेंगी एवं भारत एक महान शक्ति के रूप में एशिया एवं विश्व में उभर कर सामने आयेगा एवं अपने वर्चस्व एवं स्थायित्व की अहम भूमिका निभायेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- 1) राजनीति विज्ञान(एक समग्र अध्ययन)– राजेश मिश्रा (2021)
ऑरियन्टल ब्लैकस्वान प्रा०लि० हैदराबाद ,प्रष्ठ सं 418
- 2) वही प्रष्ठ सं 419
- 3) प्रतियोगिता दर्पण (राजनीतिक विज्ञान)– उपकार प्रकाशन(सीरीज-22)
नई दिल्ली – 2024 , प्रष्ठ सं 112
- 4) राजनीतिक विज्ञान (प्राध्यापक परीक्षा) आर०एस०आढ़ा (पिन्क सिटी
पब्लिकेशन जयपुर –2021, प्रष्ठ सं U-12
- 5) राजनीतिक विज्ञान – वी०एन०खन्ना (साहित्य भवन – आगरा –
2013)), प्रष्ठ सं